RNI Regn.No.- 54447/78 स्थापित: 1978 Postal Reg. No. UA/NTL- 08/ 2021-23

पिघलता हिमालय

वर्ष 38 अंक 52 हल्द्वानी सम्वत् 2080 सोमवार 5 जून 2023 एक प्रति 5 रु., वार्षिक-200 रु. आजीवन 2000 रु.

संस्थापक- स्व.आनन्द बल्लभ उप्रेती
स्व.दुर्गा सिंह मर्तोलिय,
स्व.श्रीमती कमला उप्रेती

editorpighaltahimalay@gmail.com
Website-
www.pighaltahimalay.com

सम्पादक : श्रीमती गीता उप्रेती
संरक्षक : फली सिंह दत्ताल
मंगल सिंह मर्तोलिया

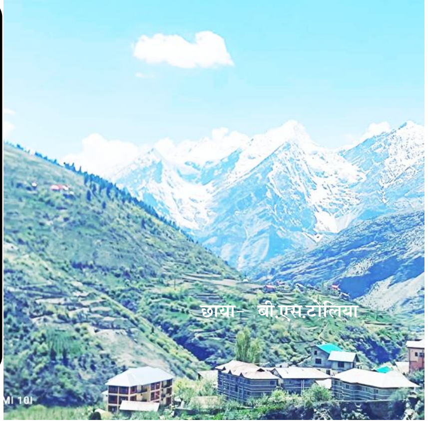

विश्व पर्यावरण दिवस पर पुनः संकल्प

गेलपातल २०२३

कपकोट के मल्लादेश में इस बार का आयोजन

कार्यालय प्रतिनिधि

5 जून को इस बार फिर से विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजन चारों ओर कई दिनों से होने लगे हैं। अपने पर्यावरण के प्रति जगरूक रहने के लिये यह जरूरी है ताकि बच्चे-बूढ़े सब सजग रहे। इस श्रृंखला में सरकारी आयोजनों के अलावा कई संस्थाओं की ओर से वृक्षारोपण व अन्य प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं। इसमें महत्वपूर्ण आयोजन जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बागेश्वर जनपद के कपकोट विकासखण्ड के ग्राम मल्लादेश में है। 'गेलपातल' याने सघन वृक्षारोपण यह अभियान हर वर्ष की भांति सोसाइटी ने इस बार मल्लादेश में रखा। प्रतिवर्ष अलग-अलग जगहों को इसके लिये चुना जाता है ताकि जन सहभागिता से यह वृहद आयोजन हो और लोग वृक्षारोपण के साथ ही इनकी सुरक्षा के लिये सजग रहें। गेलपातल भेंटघाट का आयोजन भी है ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में अपनों के बीच नेक कार्य के साथ आपसी मुलाकत भी हो।

दूरस्थ क्षेत्र मल्लादेश में जागरुकता रैली, वन पंचायत भूमि में वृक्षारोपण, बच्चों की चित्रकला, क्विज एवं भाषण प्रतियोगिता, लोक कलाकारों एवं स्थानीय कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं जोहार डॉक्टर्स एसोसिएशन के सौजन्य से नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर इस बार का मुख्य आयोजन है।

राज्य के लिए वरदान है 'मिलेट्स फूड

देवकृष्ण थपलियाल

अन्न संकट के दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों को सप्ताह में एक दिन उपवास रखने का आह्वान किया था, जिसका आम जनमानस पर गहरा असर देखने को मिला, कई लोगों नें उपवास करना शुरू किया और देश में अन्न संकट का खतरा काकी हद तक तक टल गया। उपवास भले सनातन धर्म और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा हो, परन्तु इसके शारीरिक और मानसिक लाभों को वैज्ञानिक भी खुले दिमाग से स्वीकार करते है। ठीक इसी तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपथ्य में जा चुके 'मिलेट्स फूड' मोटे अनाजों को अपने भोजन में शामिल करने का बड़ा आह्वान किया है, जो शारीरिक-मानसिक व आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से बहुत बडा क्रान्तिकारी कदम है, जिसकी प्रशंसा की जानीं चाहिए, खासकर उत्तराखण्ड जैसे पहाड़ी राज्यों में जहाँ कोदा-झंगोरा, रामदाना जैसी पोष्टिक फसलों को उगाना, लोंगों की संस्कृति व परम्परा थी, जिसका सेवन करने से घरों में ना कोई बीमार पड़ता था, ना ही किसी प्रकार की दूसरी आपदा का सामना करना पड़ता

शेष पृष्ठ 5 पर

प्लास्टिक कचरे से मुक्त होंगे सभी गाँव

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रभावी कार्ययोजना!

डॉ.हरीश चन्द्र अन्डोला

वन क्षेत्रों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के लिए वन विभाग कार्ययोजना तैयार कर रहा है। इसमें प्रवर्तन की कार्रवाई के प्रविधान पर विशेष जोर रहेगा। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर सम्बन्धित कम्पनियों के विरुद्ध भी पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। 71.05 प्रतिशत वन भूभाग वाले उत्तराखण्ड में भी प्लास्टिक, पालीथिन कचरा बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। न केवल शहरी व ग्रामीण क्षेत्र, बल्कि जंगलों में भी पसर रहा यह कचरा वन व वन्यजीव दोनों की सेहत के लिए खतरे बन रहा है। चारधाम यात्रा समेत अन्य प्रमुख मार्गो से लगे जंगलों, ईको टूरिज्म वाले स्थलों और ट्रैकिंग रूट में हर साल ही बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कचरा जमा हो रहा है। पिछले साल ही केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग से लगभग 30 क्विंटल प्लास्टिक कचरा निकाला गया था। ऐसी ही स्थिति अन्य क्षेत्रों की भी है। यही नहीं, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से लगे जंगलों के आसपास खुले में कचरा निस्तारण भी परेशानी का सबब बना है। आसान भोजन की तलाश में इसके पास धमक रहे वन्यजीव प्लास्टिक तक खा रहे हैं। पूर्व में हरिद्वार वन प्रभाग में हुए एक अध्ययन के दौरान हाथी समेत दूसरे वन्यजीवों के मल में प्लास्टिक, पालीथिन के टुकड़े पाए गए थे। इसके अलावा वन क्षेत्रों में पहुँच रहा प्लास्टिक कचरा वहाँ की भूमि की सेहत को क्षति पहुँचा रहा है। इस स्थिति पर उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए प्रभावी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। इसे देखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के निस्तारण और ठोस कचरा प्रबन्धन पर शासन ने ध्यान केन्द्रित किया है। मुख्य सचिव स्वयं इसकी मानीटरिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में वन क्षेत्रों को प्लास्टिक कचरे से बचाने के लिए विभाग को प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग के मुखिया प्रमुख मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि वन क्षेत्रों को प्लास्टिक कचरे से मुद्र करने को कार्ययोजना बनाई जा रही है। प्लास्टिक कचरे की दृष्टि से सम्वेदनशील स्थल चिह्नित किए जा रहे हैं। कार्ययोजना में वन क्षेत्रों में कचरा फेंकने अथवा छोड़ने वालों पर अर्थदण्ड लगाने के प्रविधान का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही जनजागरूकता को कदम उठाए जाएंगे। जल्द ही कार्ययोजना तैयार कर इसे शासन के सम्मुख रखा जाएगा। प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के दृष्टिगत सभी विभागों को हाईकोर्ट के आदेश को अवसर के रूप में लेते हुए इस दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में वन विभाग को भी वन क्षेत्रों के लिए एक्शन प्लान तैयार कर इसका शत-प्रतिशत अनुपालन करने को कहा गया है। गाँव-गाँव में प्लास्टिक पहुँच चुका है, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2013 में दी गई व्यवस्थाओं के तहत गाँवों में इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा था। फिलहाल तैयार कार्ययोजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर घर-घर से प्लास्टिक कचरे का एकत्रीकरण कर उसे रोड हेड तक पहुँचाया जाएगा। प्रदेश की 7791 ग्राम पंचायतों को

शेष पृष्ठ 2 पर

पव्वाधार क्षेत्र के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई

पि०हि०प्रतिनिधि

गंगोलीहाट। पव्वाधार क्षेत्र के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। बहुप्रतीक्षित पव्वाधार-नैनी-जागेश्वर मोटर मार्ग का निर्माण का शुरु होने से अब गंगोलीहाट से अल्मोड़ा जनपद की की दूरी 50 किमी तक कम हो जायेगी। इससे क्षेत्र के कई ग्रामों को सीधा लाभ होगा। क्षेत्रीय विधायक फकीर राम टम्टा ने राज्य योजनान्तर्गत 2 करोड़ 75 लाख 64 हजार की लागत से बनने जा रही साढ़े सात किमी लम्बी इस सड़क निर्माण कार्य का शुभारम्भ किया। सड़क कटिंग कार्य शुरु होने पर ग्रामीण खुशी प्रकट की है। अपने सम्बोधन में विधायक ने कहा कि गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रत्येक गाँव तक सड़क सुविधा का लाभ पहुँचाना उनकी प्राथमिकता है। शीघ्र ही क्षेत्र में लम्बित अन्य सड़कों का भी निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा। कहा कि पव्वाधार-नैनी-जागेश्वर मोटर मार्ग की मांग को लेकर क्षेत्र की जनता लम्बे समय से संघर्ष कर रही थी। वर्ष 2021 में ग्रामीणों ने सड़क को लेकर धरना-प्रदर्शन भी किया। इस सड़क के बनने से अब गंगोलीहाट की जनता को अल्मोड़ा के लिये लम्बी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्षेत्र के कई ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस सड़क पर सेरागड़ड़ के पास मोटर पुल की भी स्वीकृति मिल चुकी है। इससे पूर्व क्षेत्र की जनता ने विधायक का ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व ब्लाक प्रमुख ललित पाठक, भगवती मेहरा, भगवान सिंह डोबाल, पुष्कर बिष्ट, संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर सिंह बिष्ट, दान सिंह मेहरा भी उपस्थित थे।

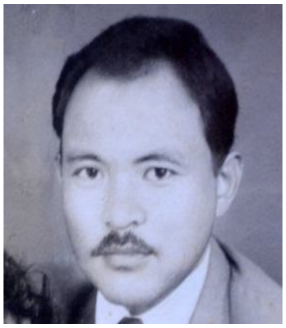

5 जून 1940 - 15 जनवरी 1989

स्व.दुर्गा सिंह मर्तोलिया

(संस्थापक पिघलता हिमालय)

की

83 वीं जयन्ती पर शत-शत नमन।

हिमालयी संस्कृति के स्तम्भ के रूप में

संकल्प के साथ

पिघलता हिमालय परिवार

एवं

परिजन

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

पिघलता हिमालय

पत्रकारिता की आड़ में माफियागर्दी

ईमान की पत्रकारिता करना मजाक नहीं है। अपने को स्वाहा कर पत्रकारिता के पेशे में आना होता है। इसके लिये कितने ही पत्र और पत्रकार मर-मिट चुके हैं। यह सब जानते हुए भी पत्रकारिता करने का साहस कौन करेगा? ईमान की पत्रकारिता में आर्थिकी संकट हमेशा रहा है। वर्तमान के दौर में बाजार को ओढ़ते हुए पत्रकारिता ने रोजी-रोटी का रास्ता बनाया है, जो अच्छी बात है। आज पत्रकारिता से हजारों लोगों के घर चल रहे हैं। लेकिन पत्रकारिता की आड़ में हो रही माफियागर्दी को सख्ती से रोकना चाहिये।

पत्रकार होने यह अर्थ नहीं है कि सारी ताकत आपको मिल चुकी है और जिसके खिलाफ चाहो बदसलूकी कर लो, धमका लो, समाचार लिखने के नाम पर ब्लैकमेलिंग करो परन्तु ऐसा देखने को मिल रहा है। पत्रकारिता की आड़ में गड़बड़ करने वाले एकदम पहचान में आ जाते हैं। इस प्रकार के कई चेहरे हमारे समाज में घूम रहे हैं। आरोप लगता है कि प्रेस की आड़ में ठेकेदारी, जंगल चोरी, खनन, नेताओं के साथ मिलकर गड़बड़ी करना, छुटभैयों के साथ मिलीभगत कर माहौल बिगाड़ा जा रहा है।

विगत दिनों हल्द्वानी में रंगदार पत्रकारों का गिरोह पकड़ा गया। न्यूज चैनल के स्टेट ब्यूरो चीफ भूपेन्द्र सिंह पन्नू सहित तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन लोगों ने सिंचाई विभाग में क्लर्क उमेश चन्द्र कोठारी से एक लाख रुपये की रंगदारी वसूल की थी। इस मामले में लगातार चर्चा हो रही है कि फर्जी पत्रकारों के तार देहरादून तक हैं। जगह-जगह ब्लैकमेलिंग कर पत्रकारिता को बदनाम करने वालों के खिलाफ पहले से भी कहा तो जा रहा था लेकिन अब जब एक बड़ा मामला खुला है तो सच्चाई दिखाई दे रही है। बड़े अधिकारी या नेता का नाम लेकर डरा-धमका कर वसूली करने वालों की पत्रकारिता क्या होती होगी? जगह-जगह आफिसों, स्कूलों, कारोवारियों से वूसली करने वाले माफियागर्दी को अपनी योग्यता मानते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि किसी पत्र के नाम पर यह मान्यता भी पा जाते हैं और इनकी दखल नेता-अधिकारियों के बीच तक हो जाती है।

पत्रकारिता और पीत पत्रकारिता के इस अन्तर को सब समझते हैं लेकिन जिस प्रकार की होड़ मच रही है वह खतरनाक है। ईमानदारी से पत्रकारिता करने वालों को संरक्षण देने कोई आगे नहीं आ रहा है। उल्टा इसकी आड़ में सौदे करने वालों से भय बना हुआ है। प्रेस का डर-भय दिखाकर समाज को दूषित करने वालों से सावधान रहना होगा। इलेक्ट्रानिक मीडिया की आड़ में तो इस लूट की अति हो चुकी है। मीडिया का नाम लेकर अनाप-सनाप पत्रकारों की भीड़ बन चुकी है, जो समाज को दिशा देने के बजाय समाज में तोड़फोड़ को प्रोत्साहित करते हैं। प्रेस की जिम्मेदारी को यह लोग नहीं जानते हैं कि समाज को बनाने, दिशा देने, न्याय दिलाने के लिये पत्रकार होता है। लेकिन आजकल इसका उल्टा दिखाई दे रहा है। आपसी सौदेबाजी, दलाली के लिये प्रेस का बैनर लेने वाले हर गलत कार्य में लिप्त हैं। पत्रकारिता को कलंकित करने वाले बहुत ही चालाकी से शासन-प्रशासन में अपनी पैठ बनाते हुए गलत ही गलत कर रहे हैं। इसलिये जरूरी है कि इस प्रकार की माफियागर्दी भी बन्द की जाए। इसके लिये जनता भी जागरुक रहे।

फसक

दाज्यू, सटर-पटर का खेल चल रहा ठैरा

किसी को फुर्सत नहीं है, दबादब लगे हैं बल

दाज्यू, ठेकेदार बूबू हरहर सिंह बहुत गुस्से में हैं और जी भर के गलिया रहे हैं। कह रहे थे- 'इनकी मादर.....फादर....कोई काम बन नहीं रहा है। लिफाफे में लपेट के थमा दिया उसके बाद थोड़ा बहुत सुनवाई हुई। गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? बच्चे क्या खाएंगे। मरने के सिवा कुछ नहीं बचा है। इनकी तो साऽले......भोगेंगे। नीचे से ऊपर तक.........।' दाज्यू, ठेकेदार बूबू की नाराजी ठीक ही हुई। पुराने आदमी हैं। उन्हें क्या पता अब ठेकेदारी का मतलब बहुत बदल गया है। अधिकारी और नेताओं की लट्ठपेल के साये में काम करना सबके बस की बात नहीं। ऊपर से दलाल अगरबत्ती जलाकर बैठे रहते हैं। किसी को फुर्सत नहीं है, दबादब लगे हैं बल। आजकल वैसे भी दो हजार का नोट बदलने के लिये अलग से समय लगाना पड़ रहा है।

अपने सीएम सैप ने ऐलान कर दिया है धार्मिक स्थलों में काम कर रहे बाहरी लोगों का सत्यापन होगा। दाज्यू, धामी जुवा नेता ठैरे। लव जेहाद और लैण्ड जेहाद पर भी कमर कस चुके हैं। समय बलवान है.........। 2024 के चुनाव से पहले सिक्के उछाले जा रहे हैं। विधायक हरीश धामी ने नैनीताल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। अजय भट्ट नाम ही बहुत ठैरा, बड़े नेता हुए। नैनीताल लोकसभा सीट पर चारों ओर डोलाडोल हो रही है।

प्रदेश सरकार जीएसवीएन-केवीएमएन वन निगम से खनन का काम छीन सकती है। राजस्व कम मिल रहा है बल। खनन दायरा बढ़ाने के लिये नई नदियों व नालों का नए सिरे से सर्वे किया जाना भी प्रस्तावित है। दाज्यू, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आँखिर क्या होने वाला है। हमारे इलाके में तो दनादन डम्फर भरकर सरासार हो रही है। पत्थर-बजरी चोर फैलते जा रहे हैं। सब कह रहे हैं खूब चोरी हो रही है लेकिन लट्ठ-मुंगर के आगे कौन बोलेगा? नौकरी करने वाले भी कर ही रहे हैं बेचारे। समय बिताना हुआ। अब दून-दिल्ली के बीच बन्देमातरम् ट्रेन भी चलने लगी है। आने वाले दिनों गोवा जाना भी आसान हो जायेगा। दाज्यू, कलजुग में तीरथ-व्रत की किसको पड़ी है। मार धिंगड़े-मिंगड़े पहन कर गोवा में घूमने का मजा और ही होता है बल। नहलाने वाले, खिलाने वाले, पिलाने वाले, मसाज वाले सबकुछ आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला हुआ। कभी हमारा बपलू भी गया था गोवा। बता रहा था- 'मालिश करने वालों ने पैर की नस-नस खोल दी। पानी में खेलने का मजा भी खूब है।' दाज्यू, दो दिन गोवा घूमने के बाद बपलू गाँव लौट आया और तब से आज तक हरे-पीले-लाल रंग के बर्फ के गोले बेच रहा है। स्कूल आते-जाते कुछ बच्चे बर्फ के गोले लेने आते हैं। बांकी दिन भर ताश के पत्ते फेंटने और वट्सएप पर बीत जाता है।

दाज्यू, हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि देश का नया संसद भवन बन चुका है। विपक्ष ने हंगामा किया लेकिन क्या होता है? जिसकी सत्ता है उसकी सुनवाई होगी या दूसरों की? मोदी ज्यू झमाझम दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं- 2024 और दे दो........। दाज्यू, अपने त्रिपाठी जी कह रहे थे- 'भारत में हलचल होना खास बात नहीं है। सौ साल के अन्तराल में खजबज होती ही है।'

आबकारी विभाग के अधिकारी निलम्बित करने पड़े। आबकारी सचिव ने उत्तरकाशी और चमोली के जिला आबकारी अधिकारियों को निलम्बित कर दिया। अल्मोड़ा के आबकारी अधिकारी पर भी कार्रवाई हो गई। शराब पी कर संचालन में लापरवाही हो रही थी बल। दाज्यू, आबकारी का मामला हुआ..... खाना-पीना लगा ठैरा। शराब की बाढ़ में कितने ही तर गये, गिनती करना कठिन है। मूरत सिंह नयी गाड़ी ले आया है। जोरशोर की पार्टी हुई। रात की पार्टी ठैरी दाज्यू। शिकार-भात वाले वर्तन तक चाटने लगे। डम्फर से लेकर बुलेरो तक सबकुछ है अपने मूरत दा के पास। कह रहे थे- 'एक बार पार्टी का टिकट मिल जाए तो इलाके को बराबर कर देंगे।' दाज्यू, मूरत दा का जबाब नहीं, सारी गनर-मनर उनके वहाँ होने वाली ठैरी। किसको प्रधान बनाना है, किसको सदस्य बनाना है, किसको जिला पंचायत और किसको विधायक.........गपोड़ी रातों रात सरकार बनाते और गिराते रहते हैं। दाज्यू, हम भी लगे हैं जब तक प्राण हैं, बनाने बिगाड़ने वाले जानें।

-तुम्हारा भुली झकरुवा

प्लास्टिक कचरे....

प्रथम पृष्ठ का शेष

प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा। धामी सरकार ने कार्ययोजना तैयार कर ली है, जिसे धरातल पर उतारने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायतों की मदद से हर घर से प्लास्टिक कूड़ा उठाने से लेकर उसके निपटारे तक की कार्रवाई की जाएगी। इस काम के लिए केन्द्र सरकार की ओर से 15वें वित्त आयोग की टाइड निधि में धन की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में उत्तराखण्ड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2013 लागू है। गाँव-गाँव में प्लास्टिक पहुँच चुका है, लेकिन एक्ट में दी गई व्यवस्थाओं के तहत गाँवों में इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा था। फिहहाल, तैयार कार्ययोजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर घर-घर से प्लास्टिक कचरे का एकत्रीकरण कर उसे रोड हेड तक पहुँचाया जाएगा। इसके बाद क्षेत्र पंचायत (ब्लाक) स्तर पर कूड़ा गाड़ियों के माध्यम से इस कचरे को काम्पैक्टर तक पहुँचाया जाएगा। अगला काम जिला पंचायतों का होगा, जो काम्पैक्ट किए गए कूड़े को निस्तारण के लिए प्लास्टिक वेस्ट प्लान्ट तक पहुँचाएंगी। यह पूरी श्रृंखला एक क्लस्टर के तहत काम करेगी जनहित याचिका पर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को गाँवों को प्लास्टिक से मुक्त बनाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराने के भी निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो अपने अधिकारियों को कूड़ा निस्तारण नियमावली की ट्रेनिंग दें, ताकि वह अपनी जिम्मेदारी जान सकें। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने होटल मल्टीप्लैक्स मॉलपार्टी लॉन यानी बैंकेट हॉल को भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि ये सभी अपने प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिलिंग प्लान्ट तक खुद लेकर जाएं। अगर वो नहीं लेकर जाएंगे तो निदेशक पंचायती राज और निदेशक शहरी विकास सम्बन्धित पर कार्रवाई करेंगे। बता दें की उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बीते दिनों उत्तराखण्ड में प्लास्टिक बैन करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश का पालन ना होता देख ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याची ने कहा था कि उत्पादनकर्ता, निर्माता, ब्राण्ड स्वामी, आयातकर्ता का प्रदूषण बोर्ड में पंजीकरण होना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि अगर ये पंजीकरण नहीं करते हैं या फिर कूड़ा निस्तारण की प्लानिंग नहीं देते हैं। इनके उत्पादों को उत्तराखण्ड में बैन किया जाए। ये अपना सामान यहाँ नहीं बेच सकते। इस आदेश का प्लान नहीं हुआ, जिस पर अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। केन्द्र व राज्य सरकार की अधिसूचना पर प्लास्टिक, थर्माकाल, स्टायरोफोम से बने 22 उत्पादों के विनिर्माण, भण्डारण, खरीद-बिक्री व उपयोग को प्रतिबन्धित किया गया था कार्यालयों में प्लास्टिक बोतल में पानी देने की कार्यसंस्कृति को समाप्त करते हुए वैकल्पिक उत्पादों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा था। स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों को प्लास्टिक से फैलने वाले प्रदूषण के बारे में अवगत कराना है। दूसरों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली जाएगी। स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायत की मदद से स्कूल परिसर से प्लास्टिक अवशेष साफ कराया जाएगा इस आदेश का प्लान नहीं हुआ, चारधाम यात्रा रूट पर प्लास्टिक बैन, नदियों को स्वच्छ रखने की कवायद साल 2022 के चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या ने सारे रिकार्ड तोड़े दिए थे। इसके साथ ही चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली थी। जिसमें कूड़ा निस्तारण की समस्या भी अहम था। खासकर हिमालय में बसे केदारनाथ के बुग्याल में फैले कूड़े की वजह से सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। लिहाजा, इससे सबक लेकर सरकार इस बार प्लास्टिक पर बैन लगाने जा रही है. इस बार यात्रा रूट पर पड़ने वाले 27 नगरों और शहरों में प्लास्टिक पूरी से प्रतिबन्धित रहेगा। चारधाम यात्रा रूट पर प्लास्टिक बैन, नदियों को स्वच्छ रखने की कवायद साल 2022 के चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या ने सारे रिकार्ड तोड़े दिए थे। इसके साथ ही चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली थी। जिसमें कूड़ा निस्तारण की समस्या भी अहम था। खासकर हिमालय में बसे केदारनाथ के बुग्याल में फैले कूड़े की वजह से सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। लिहाजा, इससे सबक लेकर सरकार इस बार प्लास्टिक पर बैन लगाने जा रही है। इस बार यात्रा रूट पर पड़ने वाले 27 नगरों और शहरों में प्लास्टिक पूरी से प्रतिबन्धित रहेगा। पहाड़ी के कई स्तरों पर कई विशेषज्ञ अध्ययन कर चुके है। यह तथ्य शहर के लोगों की चिन्ता बढ़ाने वाले हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से सम्वेदनशील उत्तराखण्ड के जंगलों की सेहत के लिए खतरा बन रहे प्लास्टिक कचरे से निबटने को अब प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उच्च न्यायालय के सख्त रुख के बाद इसे लेकर शासन और वन विभाग संजीदा हुए हैं।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

देवभूमि में

रोजगार के सशक्त विकल्प

रतन सिंह किरमोलिया

उत्तराखण्ड को देवभूमि यों ही नहीं कहा जाता है। मानसखण्ड और केदारखण्ड भी ऐसे ही नहीं कहा गया। यह अनादि काल से ही ऋषि-मुनियों, साधु-सन्तों और सन्यासियों की पावन तपस्थली रही है। दिखावे से दूर आज भी यहाँ अनेकों गिरिकन्दराओं में सैकड़ों साधु-सन्यासी गहन तपस्या करते हुए मिल जाएंगे। आज के पर्यटन की आधुनिक चकाचौंध से कोसों दूर उनकी साधना के ये तपस्थल अलौकिक शान्ति, शक्ति, ज्ञान और भक्ति के अजस्र स्रोत हैं। इनकी साधना और तप के बल पर इन स्थलों की अलौकिकता की दिव्य अनुभूमि की जा सकती है। इन स्थलों के परिवेश की अनुभूति अनायास ही सामान्य सामान्य व्यक्ति को भी ऐहिक संसार से दूर परम अलौकिक संसार का दिग्दर्शन कराने में सक्षम है।

यहाँ की पावन भूमि, अमृततुल्य जल और स्फूर्ति एवं स्वास्थ्यवर्धक समीर निश्चित ही ईश्वरीय वरदान से कमतर नहीं है। यहाँ की वनस्पतियों एवं जड़ी-बूटियों में वह शक्ति निहित है जो मृतप्राय व्यक्ति को जिला दे, प्राण सिंचन करा दे परन्तु आज के युग में इनके बारे में जानकारी के अभाव में इनकी उपयोगिता का सही मूल्यांकन एवं आम जन के हितार्थ उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस ओर चिन्तन, शोध एवं कार्य करने की सोच बन जाए तो हमारी इस देवभूमि की ख्याति विश्व पटल पर प्रकीर्ण हो जाए।

उत्तराखण्ड अपनी नैसर्गिक सुषमा से आकर्षित करता है वहीं हिमालय से लेकर हिमनद, नदी, नौले, धारे सभी इसकी जल सम्पदा को समृद्ध करते हैं। इसकी जमीन से निकलने वाला स्रोतों का जल प्राकृतिक खनिजों एवं विटामिनों से भरपूर होता है। सिंचाई एवं पेयजल के रूप में इसकी उपयोगिता है। प्रदेश ही नहीं पड़ोसी राज्य उ.प्र., बिहार और पश्चिम बंगाल आदि प्रान्तों को यह समृद्धि प्रदान करता है। जरूरत है आज इसकी इस प्राकृतिक जल सम्पदा के पुनर्चक्रीकरण, रखरखाव एवं संरक्षण करने की।

उत्तराखण्ड का 70 फीसदी से अधिक भू-भाग जंगलों से आच्छादित है। जिसमें चीड़ बहुतायत तो है ही, इसके अलावा बांज, फल्याट, अङार, बुरांश, उतीस आदि चौड़ी पत्ती के बहुत से जंगल आज भी मौजूद हैं। देशकाल परिस्थिति के अनुसार आज चौड़ीपत्ती के वनों के विस्तार की नितान्त आवश्यकता है। देखने में आ रहा है कि चीड़ के वनों की अधिकता फायदेमंद कम नुकसानदायक ज्यादा है। चीड़ से निकलने वाले पिरूल की सूखी पत्तियां गर्मियों में वनाग्नि के कारण और कारक है। ग्लोबल वार्मिंग का यह बहुत बड़ा कारण है। इससे मौसम चक्र पर भी दुष्प्रभाव परिलक्षित हो रहा हे। यदि वनों की इस आग को बचाना है तो इसका एकमात्र उपाय एक ही नज़र आता है कि इस पिरूल से कोयला बनाया जाए जो महंगे होते जा रही रसोई गैस का कारगर विकल्प सिद्ध हो सकता हैतीन दशक से भी अधिक समय से पिरूल से कोयला बनाया जा रहा है।

कुमाउंनी हास्य गीत

(तर्ज- जच्चा ने ऐसा गजब किया, अंग्रेजी फैशन सिखा दिया)

स्येणी मैसोल अब यस गजब करी हालो
अंग्रेजी फैशन सिखि हालो
आपणी मातृ भाषा सब भुलि गयीं
अंग्रेजी में बुलाण सिखि हालो
यसि बात सुणि बेर हमर वाइफ क मूड आफ हैगो
साड़ी बिलोज पैरन सब भुली गयीं
जिन्स पेरन सिखि हालो
चिट्ठी पत्री अब भुलि गयीं
मोबाइल पर बात करन सिखि हालो
भारतीय वेशभूषा धोती कुर्ता पैरन छोड़ि हालो
विदेशी पहनावा अब सिखि हालो
स्येणी मैरसोल अब राजव करि हालो
अंग्रेजी फैशन सिखि हालो
बिया काजों में सकुनांखर मंगल गीत भूलि गई
डीजे में नाचण कुदन सिखि हालो
नानतिना के सरकारी स्कूलों में हिन्दी पढ़ौन छोड़ी हालो
पब्लिक स्कूल में इंग्लिश मीडियम सिखि हालो
नानतिना अब ईजा बाव कौन भुली गई
डेडी मम्मी कौन अब सीखे हालो
लोगोल बैलगाड़ी व तांग में सफर करन भूलै हालो
बाइक व कार मे सवारी करन सिखे हालो
अब घरों व दुकानों में आले व पकौड़ी बनोण छोड़ी हालो
चाउमिन व मैगी खाण में जोर हैगो।
दूध दही धिनाली अप्राप्त हैरे
दारु पिण में बड़ जोर हैरो
पुरानी संस्कृति व रिवाज के भुली गई
नई-नई फैशन में जोर हैगा
स्येणी मैसोल अब यश गजब करी हालो
अंग्रेजी फैशन सिखि हालो।

-नन्दा बल्लभ पाण्डे
ज्योलीकोट, नैनीताल

मैंने जीना सीख लिया

उमर के इस पड़ाव पर
मैंने जीना सीख लिया
बिना किसी सहारे के
मैंने चलना सीख लिया
अब तक बांकी थी
जो हसरतें उनको
पूरा करना सीख लिया।

अब जाकर जिन्दगी का
सही अर्थ समझ आया
अधूरी सी,
उधड़ी सी जिन्दगी
को मैंने अब पूरा पाया।

अन्दर की खुशबू से
खुद को है महकाया
अब जाकर जिन्दगी का
सही अर्थ समझ आया

उम्र के इस पड़ाव पर
मैंने जीना सीख लिया
बिना किसी सहारे के
मैंने चलना सीख लिया।

-रेनू कपूर
गाजियाबाद

चस्का चाय का

बस क्या कहूँ अब, अमल तेरा गजब का
प्यारा सा चस्का लगा न्यारी सी चाय का
हे आनन्ददायिनी प्रियदर्शिनी ऊर्जा प्रदायिनी
असीम अनुभूति की जननी, तेरा सुख बहुसंख्य को भाता।
शुरुआत सुबह की नित तुमसे ही होती
उतरती हलक में अन्दर तब आवाज है खुलती
थके बदन में जब-जब आलस प्रभावी होता
संसर्ग पाकर तुम्हारा प्रिये, तन-तन नई स्फूर्ति पाता।
जाने कैसा जादू सा है तेरे इस पेय में
देकर दिव्य सुगन्ध, उमंग भर दे देह में
सुनते हैं कतिपय जन तुमको नहीं पचा पाते
तुम व्याधि की जननी हो, अनर्गल आरोप लगाते।
हैं विविध प्रकार तुम्हारे हे चायना मूल की रानी
बनाई जाए जैसी वैसे ही परिणाम प्रस्तुत कर देती हो
दूध चीनी मसाले संग सुख पाएं तुमसे कहीं कोई
कभी नींबू नमक काढ़ा कह औषधि सी बन जाती हो।

-दीवान सिंह कठायत
राईआगर, बेरीनाग

ज्योतिष की बातें - 129

7 जून 2023 को बुध मित्रराशि वृषभ में प्रवेश करेगा। वहाँ पर किसी पापग्रह की युति अथवा दृष्टि भी नहीं होगी। इसलिये बुध अत्यन्त शुभ फलदायक रहेगा। बुध बुद्धि, स्मरण शक्ति, व्यापार-वाणिज्य, गणित, लेखनकार्य, वाणी, संचार साधन, पत्र व्यवहार तथा मामा आदि का कारक होता है । बुध एक सौम्य ग्रह है इसलिए बुध के अशुभ फल उतने तीव्र एवं कठोर प्रकृति के नहीं होते हैं जितने की शनि, मंगल, राहु एवं केतु के होते हैं। बुध दूसरे, चौथे, छठवें, आठवें, दसवें व ग्यारहवें स्थान पर शुभ फल प्रदान करता है। अत: अगले 17 दिन मेष, कुम्भ, धनु, तुला, सिंह, व कर्क राशि के जातकों के लिए बुध अत्यन्त शुभ फलदायक रहेगा। शेष राशियों के लिए सामान्य फल समझना चाहिए।

यह गोचर फल नितान्त स्थूल होता है। व्यक्ति विशेष की राशि का सूक्ष्म विश्लेषण उसकी जन्मकुण्डली, महादशा आदि पर निर्भर होता है।

शुभं भवतु !!

-ओंकार नाथ कोष्टा
ज्योतिर्विद् एवं आयुर्विद

सम्यक विचार- 20

पर्यावरण संरक्षण का ढोंग

आजकल पर्यावरण की चिन्ता सभी को है। बहुत से संगठनों के द्वारा, सरकारी व गैरसरकारी संस्थाओं के द्वारा वृक्षारोपण के कार्यक्रम निरन्तर चलाए जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर पर्यावरण को हानि पहुँचाते हुए पेड़ों की कटाई निरन्तर जारी रहती है। करोड़ों छात्रों को करोड़ों पुस्तकें प्रतिवर्ष निशुल्क बांटने के लिए लाखों-करोड़ों पेड़ों की कटाई की जाती है। जो लोग वृक्षारोपण का और पर्यावरण संरक्षण का ज्ञानोपदेश देते हैं, प्राय: वही लोग जंगल का विनाश करते पाए जाते हैं। बड़े-बड़े बांधों का निर्माण आज भी जारी है जिससे सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जंगल का नाश होता है। विशालकाय गगनचुम्बी मूर्तियों की स्थापना के लिए, बड़े-बड़े आश्रमों के निर्माण के लिए विभिन्न सम्प्रदायों, संगठनों के द्वारा सैकड़ों वर्ग किलोमीटर का मैदान लाखों पेड़ काटकर समतल किया जा रहा है। सड़कें बहुत अधिक चौड़ी करने के कारण भी निरन्तर लाखों पेड़ों का कटान हो रहा है ।

जंगल काट देने से वहाँ पर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियाँ और लाखों जीव जन्तु नष्ट हो जाते हैं और वे प्राय: अन्य स्थानों पर उत्पन्न नहीं हो पाते हैं । पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाले मुख्य रूप से तीन कारण हैं- बड़े बांधों का निर्माण, जंगल का कटान और कृत्रिम बारिश। इन तीनों कारणों को रोका जाना चाहिए। 5 जून को विश्वस्तर पर पर्यावरण संरक्षण के नाम पर वृक्षारोपण नामक ढोंग किया जायेगा। वृक्षारोपण करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, धार्मिक रूप से पुण्य भी प्राप्त होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि वृक्षारोपण करने से जंगल में वृद्धि नहीं होती है अपितु जंगल में वृद्धि होती है पेड़ों के 'न काटने से'।

-सरल

बहुजन सम्वाद

उत्तराखण्ड की प्रकृति और संस्कृति पर हमला

देहरादून। बहुजन सम्वाद द्वारा किये गये सम्वाद में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखण्ड की प्रकृति और संस्कृति पर हो रहे हमले से सावधान रहना होगा। हिमालय क्षेत्र के बारे में दुनियाभर के वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि के घातक प्रभावों को लेकर चिन्तित हैं। आज हिमालय धंस रहा है लेकिन सरकारें प्राकृतिक सम्पदा के दोहन और नरसंहार वाली परियोजनाओं में धड़ल्ले से निवेश कर रही है। हिमालय पर जो कुछ बर्बादी, विनाश हो रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट चारधाम आल वेदन हाईवे, बांध, पनबिजली परियोजनाएं और इसी तरह की दूसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनओं का है। बाढ़ और बादलों के फटने से मरते और बर्बाद होते लोग, शहर और गाँव, पानी का संकट, सूखी नदियाँ, मरती खेती, प्रदूषण से मरते लोग, सिकुड़ती जैव-विविधता और सूखा सब विकराल स्वरूप धारण कर चुके हैं। सरकार को केवल बड़ी परियोजनाएं नजर आती हैं, फिर लोग मरें या जैव विविधता खत्म होती रहे, उसे फर्क नहीं पड़ता। जोशीमठ में संघर्ष जारी है। हिमालय की नदियां मलबे से भरी हैं। चारागाह पर ही, पहाड़ी खेती पर भी, रेलवे जैसे प्रोजेक्टों से हमला हो रहा है लेकिन रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की जाती।

बहुजन सम्वाद द्वारा डॉ. सुनीलम एवं डॉ. आनन्द प्रकाश तिवारी के संचालन में हुई चर्चा में सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर, पर्यावरणविद् रवि चौपड़ा, हिमालय बचाओ आन्दोलन के समीर रातुड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता इन्द्रेश मैखुरी, उपपा के अध्यक्ष पीसी तिवारी, जबरसिंह वर्मा ने विचार व्यक्त किये। चर्चा में शामिल लोगों ने कहा कि पुनर्वास क्या, नुकसान की भरपाई तक नहीं हो रही है। आज भी लोग पलायन के लिये मजबूरी हैं।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम का फार्मूला

हल्द्वानी। उत्तराखण्ड उच्चशिक्षा में ग्रीष्म अवकाश को लेकर हुई चर्चा में यह स्पष्ट किया गया है कि एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक दीक्षान्त समारोह, एक चुनाव की अवधारणा को साकार करने की प्रक्रिया के तहत सभी कालेज कार्य करेंगे। इस फार्मूले में यह तय है कि कालेजों में अवकाश एकसाथ ही होने हैं।

उच्चशिक्षा निदेशालय की ओर से समस्त प्राचार्यों को निर्देश भी जारी हो चुका है कि महाविद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा 5 जून 2023 से पूर्व किसी भी दिशा में न की जाय। महाविद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किये जाने के सम्बन्ध में निदेशालय द्वारा पृथक से सूचित किया जायेगा।

बताते चलें कि इस बार प्रवेश समेत तमाम प्रक्रियाएं समर्थ पोर्टल के द्वारा की जा रही हैं ऐसे में काफी कुछ नया होना है। नई शिक्षा नीति के अनुसार भी बदलाव होगा। शिक्षामंत्री ने दस जुलाई से कक्षाओं के लिये भी कहा है। ऐसे में कालेज प्रशासन को तैयारी में समय देना होगा।

उक्रांद की उत्तराखण्ड बचाओ रथयात्रा का संदेश

हल्द्वानी। उत्तराखण्ड क्रान्तिदल के केन्द्रीय महामंत्री सुशील उनियाल के नेतृत्व में उत्तराखण्ड बचाओ रथयात्रा जारी है। रथयात्रा का शुभारम्भ एमबीपीजी कालेज से जिला अध्यक्ष दिनेश भट्ट ने हरी झण्डी दिखाकर किया।

यात्रा का जगह-जगह स्वागत किया जा रहा है। भीमताल पहुँचने पर उक्रांद कार्यकर्ताओं ने रथयात्रा का स्वागत करते हुए कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। ऐसे में पर्वतीय राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिये आन्दोलन की आग को बनाये रखना होगा। यहाँ नवीन ममगाई, प्रेम सिंह कुल्याल, लोकेश वर्मा प्रमुख थे।

इससे पूर्व दल के केन्द्रीय महामंत्री सुशील उनियाल ने कहा कि उत्तराखण्ड में सशक्त भू-कानून बनाने, हिमालयी हितों के संरक्षण के लिये अनुच्छेद 370 लागू करने, मूल निवास 1950 का अधिकार लागू करने, गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने, जल जंगल जमीन पर राज्य के मूल निवासियों को अधिकार प्रदान करने और जानवरों से जानमाल और खेती बाड़ी की सुरक्षा के लिये पंचायत स्तर पर समाधान करने की मांग को जन-जन तक पहुँचाने के लिये रथयात्रा की जा रही है।

उन्होंने नॉन गजेटेड पदों पर सिर्फ मूल निवासियों को नियुक्ति देने, आउटसोर्स भर्ती बन्द कर मूल निवासियों को नियुक्ति देने और बड़े बांधों के बजाए रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बनाने की भी मांग उठाई।

इस दौरान चौधरी विजय पाल, गंगा जायसवाल, शिव सिंह रावत, तेज सिंह कार्की, किशन सिंह मेहता, आनन्द सिंह अस्गोला, देवेश सेन, विनोद जोशी, कुन्दन सिंह रावत, तुषार बगड्वाल,हिरदेश पोरवाल, जगदीश आर्य मुख्य रूप से रथयात्रा में शामिल रहे।

पूर्णागिरी धाम के लिये मास्टर प्लान पर कार्य

टनकपुर। जिलाधिकारी नरेन्द्र सिंह भण्डारी की अध्यक्षता में मानसखण्ड कॉरिडोर योजना को लेकर हुई बैठक में कहा गया कि जिले में प्रथम चरण में चार मन्दिरों बाराही धाम देवीधुरा, पाताल रुद्रेश्वर, बालेश्वर एवं पूर्णागिरी धाम चयनित हुए हैं। पूर्णागिरी धाम के अलग से मास्टर प्लान की परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। जिस कारण वर्तमान में मानसखण्ड परियोजना में अन्य तीन मन्दिरों का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। बैठक में कंसल्टेट्स के प्रतिनिधियों द्वारा योजना के लिए प्रस्तुतिकरण किया।

डीएम ने बाराही धाम देवीधुरा में मन्दिर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कार्य योजनान्तर्गत गहड़वाल खाम के लिये योद्धा भवन का निर्माण किया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत देवीधुरा मन्दिर परिसर में 36 कमरों वाली आवासीय सुविधा का का भी विकास किया गया है। कार्ययोजना में देवीधुरा में पर्यटक आवास गृह का निर्माण करने के बजाय देवीधुरा में लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस एवं राजस्व गेस्ट हाउस को उच्चीकृत किया जाएगा। देवीधुरा मन्दिर से नैनीताल एवं लोहाघाट की तरफ दस किमी के क्षेत्र में आकर्षक साइनेज की स्थापना भी की जाएगी। साथ ही मन्दिर समिति से समन्वय स्थापित करते हुए मन्दिर परिसर में पैदल परिक्रमा पथ विकसित किया जायेगा।

जी-२० पर सजा नरेन्द्रनगर, भ्रष्टाचार पर मंथन

टिहरी। नरेन्द्रनगर में हुए जी-20 के द्वितीय संस्करण में फिर से विदेशी मेहमानों के दर्शन हुए। नरेन्द्रनगर को मेहमानों के लिये विशेष रूप से सजाया गया था। पर्वतीय संस्कृति की झलक दिखलाते प्रतीक चारों ओर थे। वेस्टिन होटल में जी-20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक में 90 विदेशी प्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार पर मंथन किया। बैठक में 20 देशों, दस आमंत्रित देशों और 9 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया। योग से विदेशी मेहमानों के दिन की शुरुआत हुई। ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन की आरती में भी मेहमान सम्मिलित हुए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर भ्रष्टाचार का मुद्दा जी-20 का एजेंडा बताते हुए आयोजकों ने भव्य तैयारी की थी। केन्द्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने सम्मेलन की शुरुआत में कहा कि भ्रष्टाचार किसी एक देश की नहीं, यह अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। भ्रष्टाचार ने कई देशों को तबाह किया है। इसके खिलाफ अकेले लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। इसके लिये वैश्विक स्तर पर आपसी सहयोग व एकजुटता अत्यन्त आवश्यक है। केन्द्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भ्रष्टाचार से सबसे अधिक महिलाएं ही प्रभावित हैं। महिलाओं को निःशुल्क सार्वजनिक सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय सहयोग व बच्चों की देखभाल के लिए बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिये। सम्मेलन में सभी ने एक सुर में कहा कि भ्रष्टाचारी राजनीतिक शरण न ले पाएं इसके लिये सभी को एकजुट होना है।

अखाड़ा बन चुका है इंजीनियरिंग कालेज

टनकपुर। डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कालेज लम्बे समय से अखाड़ा बना हुआ है और अब फिर से निदेशक और कर्मियों में घमासान मची हुई है। कालेज के निदेशक अमित अग्रवाल और कालेज के दैनिक कर्मचारियों के बीच विवाद को सीएम कैम्प कार्यालय व पुलिस के बीच भी उठाया गया है।

निदेशक अग्रवाल ने गेस्ट फैकल्टी आलम सिंह महर, दैनिक कर्मचारी मोहित गड़गोटी और तनुजा महर पर अनुशासनहीनता और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी। दैनिक कर्मचारियों तनुजा, मोहित, मनोज शर्मा, हरीश सिंह, अनिल बाल्मिक, मोनू, तनुजा खर्कवाल, कल्पना शर्मा, हेम पोखरिया, मनीष चन्द, सुशीला गड़कोटी के अलावा फैकल्टी आलम सिंह महर ने निदेशक पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कहा है कि निदेशक गालीगलौच और अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। डरा धमका कर नियम विरुद्ध कार्य भी करवा रहे हैं। महिला कर्मियों के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है। गम्भीर आरोप लगाया है कि एक चहेती महिला कर्मी को ड्यूटी में आए बगैर वेतन दिया जा रहा है। कई कर्मचारियों को डरा धमका कर रात नौ बजे तक काम लिया जाता है। पूरे मामले पर एसडीएम और सीओ जाँच कर रहे हैं।

यह भी बताते चलें कि जिस उम्मीद के साथ क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज शुरु हुआ था, उसमें रौबदारी के अलावा विशेष कार्य नहीं हो पाये हैं। निदेशक कालेज के पक्ष में दावे करते रहे हैं लेकिन उनकी खिलाफत बहुत ज्यादा है।

छोटी हल्द्वानी, कुआंडांठ, हुड़किया चौक नपं में

हल्द्वानी। कैबिनेट ने कालाढूंगी नगर पंचायत का दायरा बढ़ाने पर जैसे ही सहमति दी क्षेत्रवासियों ने विधायक बंशीधर भगत का फूलमालाओं से स्वागत किया। अब नगर पंचायत का दायरे में छोटी हल्द्वानी, कालाढूंगी कन्दोबस्ती, कुआंडाट एवं हुड़किया चौड़ नगर भी आ गए हैं। नगर पंचायत पर शामिल होने पर इन क्षेत्रों पर विधायक बंशीधर भगत का अभिनन्दन किया गया।

श्री भगत ने कहा कि 1974 में गठित कालाढूंगी नगर पंचायत में वर्तमान में सात वार्डों में 7200 की आबादी है। छोटी हल्द्वानी एवं कालाढूंगी बन्दोबस्ती क्षेत्र को नगर पंचायत में जोड़ने से लगभग दस हजार की आबादी नगर पंचायत के दायरे में आ जाएगी। इनको नगर पंचायत से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 5854 मतदाताओं वाली कालाढूंगी नगर पंचायत में अब लगभग 2200 मतदाताओं के और जुड़ने का अनुमान है।

विधायक का सम्मान करने वालों में मण्डल अध्यक्ष विक्रम सिंह जन्तवाल, विनोद बुडलाकोटी, हरीश मेहरा, पुष्कर कत्यूरा, धर्मानन्द रखोलिया आदि थे।

बताते चलें कि हल्द्वानी से अलग होकर जब कालाढूंगी विधानसभा बनी तब से बंशीधर भगत लगातार यहाँ के विधायक बने हैं। यह पूरा क्षेत्र भाजपा के दबदबा वाला माना जाता है। ऐसे में हर रणनीति को राजनीति से भी तोलने का आरोप है।

परिक्रमा

रुद्रपुर के ओबीसी सर्वे पर जताई आपत्ति

रुद्रपुर। ओबीसी आरक्षण को लेकर नगर निगम रुद्रपुर, नगरपालिका गदरपुर, किच्छा एवं नगर पंचायत कैलाखेड़ा, दिनेशपुर, गुलरभोज के निर्वाचित प्रतिनिधियों व जन सामान्य की सुनवाई के दौरान नगर निगम रुद्रपुर में करये सर्वे पर कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। इस पर आयोग के अध्यक्ष ने सर्वे के निर्देश दिये

हरिद्वार में पूरी चौकी लाइन हाजिर

हरिद्वार। सड़क हादसे में दो लोगों की मौत के मामले में लापरवाही बरतने के मामले में एसएसपी अजय सिंह ने प्रभारी समेत पूरी चौकी को लाइन हाजिर कर दिया। चौकी भिक्कनपुर क्षेत्र अन्तर्गत ट्रैक्टर-ट्राली की चपेट में आने से एक व्यक्ति व बच्चे की मृत्यु एवं एक बच्चे के घायल हो जाने की घ्टना की रिपोर्ट के आधार पर यह कदम उठाया गया।

दस जून तक रोडमैप बन जायेगा

हल्द्वानी। जिलाधिकारी वन्दना सिंह ने शहर में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा करतते हुए लोनिवि से दस जून तक फ्लाईओवर को लेकर सम्बन्धित संस्था के साथ रोडमैप बनाकर प्रस्तुत करने को कहा है। लोनिवि को रामपुर रोड और कमलुवागांजा रोड का फोरलेन के तहत सर्वे का कार्य भी करना है।

साढ़े चार घंटे में देहरादून से दिल्ली

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्चुअल हरी झंडी दिखाते ही देहरादून-दिल्ली बन्दे भारत एक्सप्रेस चालू हो चुकी है। यह रेल सप्ताह के 6 दिन (बुधबार को छोड़कर) संचालित होगी और साढ़े चार घण्टे में दूरी तय हो जायेगी।

बिन्दुखत्ता राजस्व गाँव बनाने की मांग

हल्द्वानी। भाकपा माले ने एक बार फिर से बिन्दुखत्ता को राजस्व गाँव बनाने की मांग उठाई है। माले की नैनीताल जिला कमेटी बैठक में सभी वन भूमि में बसे खत्तों, गुर्जरों, गोठ का नियमितीकरण किये जाने की मांग उठाई। जिला सचिव कैलाश पाण्डे ने कहा कि बिन्दुखत्ता ने अपना अस्तित्व संघर्ष के बल पर खड़ा किया है।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

नौ छावनी परिषदों की विस्तृत रिपोर्ट की विस्तृत रिपोर्ट मांगी

रानीखेत। शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य की नौ छावनी परिषदों के शिविल एरिया को नगर पालिका में पृथक किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री मोहन नेगी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने देश की 62 छावनी परिषदों के सिविल एरिया को नगर पालिका में मिलाए जाने के लिए सम्बन्धित राज्यों के नगर विकास मंत्रालय से सिविल क्षेत्र का क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं दिशावार विवरण स्पष्ट करने को कहा। उल्लेखनीय है कि मई 2022 में भी रक्षा मंत्रालय ने इस बावत विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा था लेकिन कई छावनियों के सम पर प्रस्ताव नहीं पहुँचे। अब फिर से रक्षा मंत्रालय ने राज्य के 5 जिलों देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा के जिलाधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा है। भेजे गये पत्र में शहरी विकास मंत्रालय के अनुसचिव अनिल काला ने जिलाधिकारियों से कहा है कि प्रस्ताव में सिविल क्षेत्र का क्षेत्रफल, जनसंख्या, दिशावार विवरण स्पष्ट कर अतिशीघ्र विस्तृत आख्या शासन को उपलब्ध कराएं। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित करने के बाद छावनी क्षेत्रों के सिविल एरिया के प्रस्ताव राज्य को सक्षम अथॉरिटी माध्यम से रक्षा मंत्रालय को प्रेषित की जानी है।

विगत दिनों रानीखेत के एक शिष्ट मण्डल ने केन्द्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट से भेंट की थी। उन्होंने भी राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने की बात कही थी। अब यदि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सिविल एरिया को नगर पालिका में मिलाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास करके रक्षा मंत्रालय को भेजा जाता है तो अतिशीघ्र छावनी के सिविल एरिया में निवास करने वाले नागरिकों को कैंट के कठारे कानूनों से मुक्ति मिल जाएगी।

बताते चलें कि रानीखेत वासियों द्वारा छावनी एरिया से बाहर करने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चिलियानौला नगर पालिका बनाये जाने के बाद भी रानीखेत का बड़ा हिस्सा इसमें शामिल नहीं हो पाया और छावनी परिषद के कड़े नियमों के कारण निर्माण कार्यों में कई प्रकार की दिक्कतें होती है। क्षेत्रवासियों का तर्क है कि विकास के लिये कैंट से मुक्ति जरूरी है ताकि सिविल एरिया का विकास अपने तरीके से हो।

अतिक्रमण हटाओ अभियान। हल्द्वानी, रामनगर, किच्छा, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर में गरज रही है जेसीबी

प्रदेश में चारों ओर चलाये जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान की हलचल है। हल्द्वानी महानगर के बाजार में जेसीबी कब्जे हटाये गये। नगर निगम और पुलिस ने बाजार क्षेत्र में लगातार अभियान चलाते हुए सड़कों को घेरे बैठे लोगों को चेतावनी दी, चालान काटा और सामान जब्त भी किया। नगर आयुक्त पंकज पाण्डे ने कहा कि फुटपाथ, नाली घेरने वाले नहीं छोड़े जाएंगे। मुखानी क्षेत्र में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाते हुए चालान काटे।

रामनगर शहर में भी ताबड़तोड़ कब्जे हटाये गये। ग्राम ढिकुली में सिंचाई नहरों के किनारे रिसॉर्ट, रेस्तरां एवं अन्य लोगों द्वारा किये गये अतिक्रमण हटाए गए। सिंचाई विभाग ने अपनी नहरों को जेसीबी से अतिक्रमण मुक्त किया। इसके लिये गुलरघुट्टी में बड़ा अभियान चला। किच्छा शहर के हल्द्वानी मार्ग पर महाराणा प्रताप चौक से लेकर बेनी मजार तक दर्जनों व्यापारियों व स्थानीय लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस मिला है। इसके अलावा बाजार में पुलिस व प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है।

नैनीताल शहर में बाहरी राज्यों से आए हुए लोगों द्वारा मालरोड, पन्त पार्क में व्यवसाय किये जाने की सूचना पर सत्यापन कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया। नगर पालिका का कहना है कि अवैध तरीके से शहर में व्यापार करने वालों पर कार्रवाई हुई है।

काशीपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। महुआखेड़ा गंज में तालाबों पर हुए कब्जे हटाने के लिये जेसीबी मशीनें लगाई गई। एक तालाब की भूमि पर कब्जा कर बनी बर्फ फैक्ट्री को भी ध्वस्त किया गया।

जसपुर में अभियान के दौरान कई लोगों ने अपने अतिक्रमण स्वयं हटा लिये। जसपुर-नादेही चीनी मिल माग पर प्रशासन ने 24 दुकान, मकान व अन्य अवैध निर्माण ध्वस्त किये। अतिक्रमण हटाओ टीम ने सड़क के मध्य फीता डालकर दोनों ओर सड़क की सीमा नापते हुए अतिक्रमण हटाने का ऐलान किया। ऐसे में कुछ लोगों ने स्वयं ही अपना सामान समेट लिया।

पीड़ित लोगों को अन्यत्र बसाएं : बेहड़

किच्छा। विधायक तिलकराज बेहड़ ने नगर के तमाम क्षेत्रों में अतिक्रमण की जद में आए प्रभावित लोगों को विस्थापित करने की मांग को लेकर डीएम जुगल किशोर पन्त से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से एक स्थान पर रोजी-रोटी के लिये प्रतिष्ठान चलाकर अपना जीवन यापन करने वालों को एकाएक उजाड़ना गलत है। ज्ञापन सौंपने वालों में किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष दर्शन कोली, नगर कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी बबलू भी थे।

फिलहाल वनग्राम, गोठ खत्ते नहीं हटेंगे

अतिक्रमण के नाम पर फिलहाल वनग्राम, गोठ, खत्ते नहीं हटाये जायेंगे। अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अधिकारी मुख्य वन संरक्षक ने सभी वन प्रभागीय अधिकारियों को पत्र जारी कर आदेश दिया है। बताते चलें कि अभियान के तहत सभी के पास नोटिस पहुँच गये थे और जिससे खत्तेवासी परेशान हो चुके थे और सरकार से अपील कर रहे थे।

विधायक कार्यालय का घेराव

रामनगर। शासन के निर्देश पर अतिक्रमण की जद में आ रहे सैकड़ों लोगों ने घर बचाओ मुहिम चलाते हुए रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय को घेर लिया। विधायक पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। धरना देते हुए आक्रोशित लोगों ने कहा कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों का संरक्षक होता है और उनका दायित्व है कि लोगों की दिक्कतों को सुने तथा सरकार से उनका समाधान कराएं। प्रदर्शनकारियों में वन ग्राम समिति के संयोजक एस.लाल, ज्येष्ठ ब्लाक प्रमुख संजय नेगी, उपपा के महासचिव प्रभात ध्यानी, आप के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत भी थे।

रणजीत रावत के नेतृत्व में प्रदर्शन

रामनगर। अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़े जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल रैली निकाली। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर रैली वन परिसर पहुँची। जनसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उपस्थित जनों से इस मामले में सीएम से वार्ता करने और प्रकरण को विधानसभा में भी उठाने का आश्वासन दिया। रणजीत रावत ने सरकार के इस आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि यदि सरकार अब भी नहीं मानी तो जनता सड़कों पर उतरेगी। पूर्व सांसद डॉ.महेन्द्र पाल, पालिकाध्यक्ष मो.अकरम, किशोरीलाल ने भी सभा को सम्बोधित किया।

राज्य के लिए.....

प्रथम पृष्ठ का शेष

था। आज तथाकथित आधुनिक और सभ्य कहे जानें वाली नई पीढ़ी इनको उगाना तो छोड़ दीजिए लोग खाने से भी कतराने लगे हैं, इन फसलों नें जहाँ हमारे पूर्वजों कों स्वस्थ व दीर्घायु रखा वहीं किसी भी घर को भूखमरी या भीख मांगने की जैसी दुर्दशा से बचाए रखा, पहाड़ की आन की आन-बान-शान कहे जाने वाले कोदा-झंगोरा, कोंणी, चौलाई अन्य पारम्परिक फसलों से निर्मित भोजन आज हमारी थाली से विलुप्त हो चुका है। इन उत्पादों में आज के भोजन गेहूँ-चावल के मुकाबले कई गुणा ज्यादा कैल्सियम, आइरन, फास्फोरस जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं। पहाड़ में कहावत है, 'मो पालिज्यो मंडुवा भ्यो' अर्थात परिवार के भरण-पोषण करने वाला मुख्य सहारा मंडुवा ही है।

प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा वर्ष 2023 को अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष' घोषित किया गया है जो इन मॉर्डन कहे जाने वाले लोगों को आईना दिखानें जैसा है, ये वे लोग हैं, जो मिलेट्स फूड अथवा मोटे अनाज के भोजन को गरीबों और पिछड़ों का भोजन मानते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि मिलेट्स फूड के कई गुना फायदे हैं। देश में डाइबिटिज, मोटापा तेजी से बढ़ रहा, जैसी बीमारियाँ तेजी के लिए मिलेट्स फूड रामवाण का काम करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट आर्फ फूड टैक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिय एंड मैनेजमेंट तंजावुर ने अभी हाल में मोटे अनाज को लेकर चेन्नई में 'मोटे अनाज सम्मेलन' अथवा 'मिलेट समिट-2023' का आयोजन किया, जिसमें शामिल देश-विदेश के सभी विशेषज्ञों ने एक स्वर से मिलेट्स फूड के लाभों को स्वीकार किया, साथ ही आने वाले समय के लिए मिलेट्स फूड के भविष्य की बात कही। देशभर के कृषि वैज्ञानिक भी अब मोटे अनाज की महत्ता को समझने लगे हैं। इससे देश का किसान और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो दूसरी ओर देश स्वस्थ होगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी को सन्देह नही है कि मोटे अनाज का उत्पादन, खपत, प्रसस्करण, निर्यात और इसमें प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ेगा। देश के दो राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलेट्स फूड' की असीम सम्भावनाएं हैं। बिहार को 2015-16 में मोटे अनाज के वर्ग में पूरे देश में सर्वोच्च उत्पादन के लिए 'कृषि कर्मण पुरूस्कार' दिया जा चूका है। देश में मोटे अनाज का समृद्ध इतिहास रहा है। ये अनाज मुख्यत: ज्वार, बाजरा, मंडुवा, जौ, सांवा, कुटकी, कामनीं आदि जैसी फसलें हैं, फूड एण्ड एग्रीकल्चर आर्गिनाइजेजन(एफएओ) के अनुसार मिलेट्स फसलों को विश्व में 75.70 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता है, जिसका उत्पादन 90.35 मिलियन मिट्रिक टन है। भारत मिलेट्स फूड फसलों का पाँचवा सबसे बड़ा निर्यातक है। लेकिन उत्पादन इससे ज्यादा है, साल 2020 में भारत का वैश्विक उत्पादन में 41 प्रतिशत योगदान था। किन्तु पिछले पचास-साठ सालों से देश में मोटे अनाज का सेवन उत्तरोत्तर घटा है। 1960 से 2018 तक मोटे अनाज का क्षेत्र 9.02 मिलियन हैक्टेयर से घटकर 7.38 मिलियन हैक्टेयर हो गया है।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विगत माह 13 से 16 मई तक राजधानी के हाथीबड़कला में मिलेट्स फूड को लेकर श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया, जो जन जागरूकता की दृष्टि से जरूरी था ताकि मोटे अनाज को लेकर लोगों में फैली भ्रान्तियों को दूर किया जा सके। इस सम्मेलन में भी पहुँचे तमाम राज्य-केन्द्रीय मंत्रियों और जानकारों नें भी एक स्वर में मिलेट्स फूड्स' अथवा मोटे अनाज के महत्व को स्वीकार किया। वहाँ पहुँचे तमाम लोगों ने भी सप्ताह में एक दिन मोटे अनाज लेंनें का संकल्प लिया। निश्चित रूप से मिलेट्स फूड के लिए आयोजित इस उत्सव से विलुप्त हो रही इन फसलों को बढ़ावा मिलेगा तथा रचनात्मक माहौल बनेगा।

अब बारी ये है कि सरकार मिलेट्स फूड्स को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या करती अथवा महज भाषण तक सीमित रखती है? उत्तराखण्ड राज्य देश का तीसरा राज्य है, जिसने मिलेट मिज़न की शुरूवात की है, वही घोषणा कि गई कि मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए जगह-जगह मार्ट खोले जाएंगें। चार धाम और दूसरे मन्दिरों में प्रसाद के रूप में मोटे अनाजों का इस्तेमाल किया जायेगा। इससे जहाँ मोटे अनाज की खपत बढ़ेगी वहीं आम लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे, किसानों को एक सशक्त मंच मिलेगा। अगर इसी तरह प्रोत्साहन व फसल का उचित मूल्य मिलेगा तो किसान मोटे अनाजों को उगाने के लिए उत्साहित होंगे क्योकि आमतौर से इन फसलों को उगाने के लिए कोई खास श्रम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये फसलें कम उपजाऊ भूमि में भी आसानी से पैदा हो जाती हैं। इसके लिये जरूरी है कि सरकार उसके लिए बाजार तैयार करे ताकि किसानों को इसका उचित मूल्य मिले, जगह-जगह मार्ट और दूसरी तरह की कम्पनियों को खोला जाए। पतंजलि योगपीठ मोटे अनाज उत्पादों के लिए बड़ा प्लेटफार्म बना रहा है। कृषि मंत्री बताते हैं, सरकार ने बजट में मोटे अनाज के प्रोत्साहन के लिए करीब 73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा इसके मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थो के सेवन में जो कठनाई है वह भी दूर होगी।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

विश्व पर्यावरण दिवस व जोहार खेलोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं-

उत्तम सिंह पांगती

सेनि.जज

जोहार नगर, हल्द्वानी

खजान गुड्डू

पूर्व दर्जा मंत्री

उत्तराखण्ड सरकार

हल्द्वानी

डॉ.बी.आर.पन्त

हरिपुरपूर्णानन्द, पो.अर्जुनपुर

हल्द्वानी

एम.डी.एम. एजूकेशनल एकेडमी

ककराली गेट,

टनकपुर

(चम्पावत)

होटल माँ नन्दादेवी एण्ड बारात घर

नानासेम, मुनस्यारी

गणेश सिंह मर्तोलिया एण्ड सन्स

मुनस्यारी

हार्डवेयर, बिल्डिंग मैटीरियल एवं जनरल आर्डर सप्लायर्स

फोन सम्पर्क- 05961-222236

8958525979, 9411134775

सप्ताह के पर्व

ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष

15 मई- ज्येष्ठ आरम्भ
15 मई- अपरा एकादशी व्रत
19 मई- वटसावित्री व्रत
19 मई- अमावस्या

Hotel Bala Paradise

Tiksain, Munsiari

Ph. 05961222237, 9412951678

Enjoy Beauty of Himalaya at

MARTOLIA LODGE

Family Guest House- Sarmoly, Munsiyari

A Home Away From Home & Home Stay

Phone: (05961) 222287

धमोत होम स्टे

धरमघर/चकोड़ी

(एडवेंचर जोन, ट्रेकिंग,माउंटेन वाइकिंग, स्थानीय व्यंजन)

मो. 9760007148

www.mountainheights.in

MARTOLIA FURNITURE

A unit of Martolia Enterprises

Pilikothi Haldwani

Mob- 8057167777, 7906752084, 8650427229

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीमती गीता उप्रेती द्वारा पिघलता हिमालय, जे०के०पुरम्, सेक्टर डी, छोटी मुखानी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड से प्रकाशित एवं शक्ति प्रेस, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) से मुद्रित।

सम्पादकः श्रीमती गीता उप्रेती

फोन/फैक्सः (05946) 264013, 9458961490, 9411770280, 9411301014, 9410713075,

editorpighaltahimalay@gmail.com

Website- www.pighaltahimalay.com

पत्र व्यवहार के लिये पते-

जे0के0पुरम्, सेक्टर डी, छोटी मुखानी, हल्द्वानी (नैनीताल)

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)